भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2005

28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

जलापूर्ति और स्वच्छता की स्थिति

2005. श्री हुसैन दलवई:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जलापूर्ति और स्वच्छता पर डब्ल्यू. एच. ओ., यूनिसेफ एवं विश्व बैंक द्वारा कराए गए कई स्वतंत्र आकलन ने भारत में इसकी दयनीय स्थिति की ओर इशारा किया है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य–वार क्या ब्यौरा है;
(ग) इस स्थिति को सुधारने हेतु विगत में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(घ) जहां तक जलापूर्ति और स्वच्छता का संबंध है तो क्या वर्तमान सरकार पहले से चल रहे कार्यक्रमों को समाप्त करने की मंशा रखती है; और
(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) एवं (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकाल निधि (यूनीसेफ) द्वारा प्रकाशित अद्यतन संयुक्त मॉनिटरिंग कार्यक्रम (जेएमपी) रिपोर्ट, 2014 के अनुसार, 2012 में 91 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को उन्नत पेयजल स्रोत की तथा 35 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध थी। यह आंकड़ा, अनेक डाटा स्रोतों से तैयार किए गए जेएमपी के अनुमानों पर आधारित है। यह सूचना राज्य-वार उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की ग्रामीण आबादी को निरंतरता के आधार पर उन्नत पेयजल स्रोतों द्वारा स्वच्छ एवं पर्याप्त पेय जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो, भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) का संचालन करती है, जिसके द्वारा राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी जाती है ताकि पाइप द्वारा जलापूर्ति स्कीमों से पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और ग्रामीण आबादी को हैण्डपंपों जैसी स्कीमों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के उनके प्रयासों में सहायता मिल सके। एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत, राज्यों को उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं में गुणवत्ता प्रभावित तथा आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल से कवर करने को प्राथमिकता दी जाती है। 2014-15 में एनआरडीडब्लूपी के लिए 11,000 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, सात राज्यों में विदेशी सहायता से ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाएं चल रही हैं।

इसके अलावा, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से असम, बिहार, झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में कम आय वाले राज्यों के लिए ग्रामीण पेयजलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं (आरडब्लूएसएसपी-एलआईएस) की शुरूआत की गई है।

भारत सरकार, ग्रामीण भारत में स्वच्छता में सुधार लाने के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम निर्मल भारत अभियान (एनबीए) नामक कार्यक्रम का संचालन करती है। एनबीए के अन्तर्गत स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएलएस) के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के अतिरिक्त, पहचाने गए गरीबी रेखा से ऊपर के (एपीएल) परिवारों तक बढ़ाया गया (सभी अनुसूचित जाति/जनजाति, छोटे और सुविधाहीन किसान, अधिवास वाले भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला आश्रित परिवार)
- एनबीए के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, 3200/- रू. की पूर्ववर्ती राशि को बढ़ाकर 4600/- रू. कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शौचालय के निर्माण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत 5400/- रू. तक का उपयोग किया जा सकता है, 900/- रू. के लाभार्थी अंशदान के साथ-साथ शौचालय की कुल इकाई लागत अब 10,900/- रू. है (पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 11,400/-रू.)
- जिला परियोजनाओं के कुल परिव्यय में से चिन्हित 15% की राशि के साथ सूचना, शिक्षण और संप्रेषण (आईईसी) पर अधिक बल दिया जा रहा है।
- ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के साथ संयुक्त दृष्टिकोण।
- स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण सहित संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण स्वच्छता (एनबीए) के तालमेल पर बल देना।
- मनरेगा के साथ तालमेल करके ठोस तथा तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्लूएम) के घटक को परियोजना आधारित दृष्टिकोण में बदलना।
- स्वच्छता के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना, 12वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय 37159 करोड़ रू. पर निर्धारित किया गया है, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय के 6540 करोड़ रू. से 468% अधिक है।

(घ) जी नहीं।

(ड.) प्रश्न ही नहीं उठता।

****

अनुलग्नक

दिनांक 28.07.2014 को उत्तर दिए जाने हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2005 के भाग (क) एवं (ख) में उल्लिखित विवरण

एनएसएसओ 2012 के अनुसार शौचालयों की सुविधा वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ग्रामीण परिवार

क्रम.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शौचालय की सुविधा वाले ग्रामीण परिवारों का %
1	आंध्र प्रदेश	45.7
2	अरूणाचल प्रदेश	87.4
3	असम	86.3
4	बिहार	27.2
5	छतीसगढ़	23.3
6	गोवा	90.3
7	गुजरात	41.3
8	हरियाणा	74.6
9	हिमाचल प्रदेश	74.3
10	जम्मू एवं कश्मीर	55.7
11	झारखण्ड	9.5
12	कर्नाटक	29.2
13	केरल	97.2
14	मध्य प्रदेश	21.0
15	महाराष्ट्र	46.0
16	मणिपुर	98.8
17	मेघालय	95.5
18	मिजोरम	99.3
19	नागालैंड	100.0
20	ओडिसा	18.7
21	पंजाब	77.8
22	राजस्थान	27.0
23	सिक्किम	99.8
24	तमिलनाडु	33.6
25	त्रिपुरा	98.6
26	उत्तर प्रदेश	24.7
27	उत्तराखण्ड	80.3
28	पश्चिम बंगाल	60.3
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	71.2
30	चंडीगढ	99.7
31	दादर और नगर हवेली	50.7
32	दमन एवं दीव	73.2
33	दिल्ली	100.0
34	पुदुचेरी	52.6
	समस्त भारत	**40.6**